एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 04, अंक: 03 (मई-जून, 2024)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाएं: एक नजर

(*प्रीत गिल एवं डॉ. कविता दुआ)
आई. सी. कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
*संवादी लेखक का ईमेल पता: preetgill43210@gmail.com

महिला सशक्तिकरण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल महिलाओं को अधिकारों की दिशा में अधिक संवेदनशील बनाता है, बल्कि समाज को भी पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ाता है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और समाज में समानता के अधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए।

महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें निर्धारित विचारशीलता और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज के संरचनात्मक और आर्थिक विकास की दिशा में नई दिशा देता है।

महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं को उत्थान करने के लिए, सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वायत्तता के लिए संबल दिया जा रहा है। यहां हम कुछ मुख्य सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे:

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से, शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन तीन मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, और मानव संसाधन मंत्रालय शामिल हैं।

स्त्री शक्ति योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाना है ताकि वे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अग्रसर हो सकें। इस के लिए, एसबीआई बैंक महिलाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतंत्रता के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

महिला उत्थान योजना: 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना' सितंबर 2013 से प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत, उन्हें कौशल विकास, वित्तीय सहायता, और उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

महिला कोइर योजना (Women's Choir Scheme) में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, महिलाओं को कायर स्पिनिंग में दो महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही, महिलाओं को मासिक भत्ता 3,000 रुपये भी प्रदान किया जाता है। अगर कोई महिला नारियल की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए सरकार द्वारा 75 फीसदी तक का ऋण भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को शुरू हुई, लकड़ी और कोयला जलाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने का उद्देश्य रखती है। इसके तहत, केंद्र सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को लाभ मिल सके।

फ्री सिलाई मशीन योजना: केंद्र सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरूआत की है, जिससे सिलाई-कढ़ाई में रुचि रखने वाली महिलाओं को सहायता मिले। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है। आवेदन करने की योग्यता के लिए महिलाओं की आय 12,000 रुपये से कम होनी चाहिए और उनकी आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुद्रा लोन योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में महिला उद्यमियों की संख्या को बढ़ाना है। इसके माध्यम से, महिलाएं सूक्ष्म और लघु उद्योगों की शुरुआत कर सकती हैं। इस योजना के तहत, महिलाओं को दस लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है और उन्हें उनके अधिकारों का अनुभव करने में मदद की जा रही है। यह सभी योजनाएं महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास में मदद करती हैं और उन्हें समर्थ बनाती हैं अपने भविष्य को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ निर्मित करने के लिए। इसके अलावा, ये योजनाएं समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देती हैं और उन्हें सक्षम बनाती हैं स्वयं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, और उन्हें समाज में उनकी सहायता और समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, महिलाएं अपनी सकारात्मक स्थिति को स्थायी रूप से सुधार सकती हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसलिए, हमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समृद्ध और समान भारत की दिशा में अग्रसर हो सकें।